

जी-7 वभिजन की राह पर

संदर्भ

8-9 जून, 2018 को क्यूबेक, कनाडा में आयोजित हुए संगठित समूह G-7 की बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के रुख के कारण वभिजित और उलझन में दिखाई दिये। विश्व व्यवस्था को नयित्तरति करने के लिये इन सातों के बीच समझौता अब संकट की स्थिति में दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा लंबे समय से इस समूह के नियमों के साथ खलिवाड़ किया जा रहा है।

पछिले कुछ दशकों में समूह ने दुनिया को क्या दिया है?

- सामूहिक और व्यक्तगत रूप से यह समूह ज़्यादातर विकासशील देशों के खर्च पर विकसित हुआ है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का उद्देश्य अपने प्रशासन में व्याप्त बाधाओं का समाधान करते हुए उभरते बाज़ारों को विश्व पटल पर लाना है।
- अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) ने अपने कृषि बाज़ारों के लिये प्रतस्पर्द्धा की अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने ब्राज़ील और भारत जैसे उभरते बाज़ारों पर दबाव डालने के लिये करों को कम करके आयात में कमी की है।
- इन देशों ने अपने प्रभाव और रुचि को बनाए रखने के लिये गरीब देशों के बीच वभिजन की स्थिति उत्पन्न की।
- वे चीन के असाधारण रूप से वनिरिमाण के क्षेत्र में उभरने को लेकर बेहद चिन्तित थे, जो धीरे-धीरे उनकी क्षमताओं को आत्मसात करता जा रहा था।
- समूह की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण चीन पश्चिम में आइना दिखाने में कामयाब रहा।
- गरीब देशों की मदद करने की अपनी सभी प्रतबिद्धताओं को नज़रंदाज करते हुए जी-7 अभी भी लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों को अपने उत्पादों के बाज़ार के रूप में देखना चाहता है।
- इसने विकासशील देशों में औद्योगीकरण में वृद्धि की संभावनाओं का उपहास उड़ाया है। चीन की वनिरिमाण क्षमताओं को विकसित करने वाले अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के दो या तीन देशों के प्रभाव को आसानी से समझा जा सकता है।
- चीन और भारत के उदय पर ये देश खुश नहीं होंगे। इसलिये, वे इन दोनों देशों के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों को उभरता हुआ देखना पसंद नहीं करेंगे।
- वे पहले ही भारत और चीन पर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। घरेलू उत्पादन और वनिरिमाण के प्रोत्साहन को लेकर यूरोपीय संघ भारत से परेशान है।
- भारत ने पूरी तरह से देश में नरिमति कारों पर उच्च टैरिफि लगाया है। भारत ने अपने घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग को वस्तितार देते हुए और इसे गहराई की ओर ले जाने के लिये प्रयास कर रहा है।
- भारत में बनाई गई कारें और इनके पार्ट्स दुनिया भर में बेचे जाते हैं। यूरोपीय और अमेरिकी ऑटो कंपनियों ने भारतीय बाज़ार में अपनी हस्सिसेदारी सुनश्चिति करने तथा उनके उत्पादों से प्रतस्पर्द्धा करने के लिये अरबों रुपए नविश किये हैं।
- अब भी, यूरोपीय संघ पूरी तरह से वहाँ नरिमति कारों पर कम आयात शुल्क के लिये दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ यह चाहता है कि भारत यूरोप में इसतेमाल की जाने वाली कारें खरीदे।
- इसी तरह, अमेरिका अपनी सौर-नरिमाण क्षमताओं को बढ़ावा देने के प्रयासों के बारे में भारत को परेशान कर रहा है। उसे यह पसंद है कि भारत वनिरिमाण की बजाय आयात करे।
- मई में अमेरिका ने वभिनिन योजनाओं के माध्यम से अपने नरियात को बढ़ावा देने के लिये भारत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चीन और भारत भी आपस में लड़ रहे हैं।
- भारत ने भी आयातित स्टील पर शुल्क बढ़ाने के लिये अमेरिका के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में मामला दर्ज किया है।

चीन का मज़बूत दृष्टिकोण

- चीन ने नश्चिति रूप से अपने दृष्टिकोण पर काफी मज़बूती दिखाई है। इसने जी-7 द्वारा नरिधारित नियमों को मानने से इनकार कर दिया है।
- भारत इसका वरिध कर सकता है क्योंकि चीन की बेल्ट और रोड पहल उसी तरह का आर्थिक साम्राज्यवाद है जसि जी-7, वशिष रूप से ब्रिटेन ने सदयियों से दुनिया पर लगाया था।
- अब एशियाई देश परिक्व हो गए हैं, पश्चिमी बाज़ारों को समान नीतियों का सामना करना पड़ रहा है जनिका उपयोग उन्होंने दुनिया को नयित्तरति करने के लिये किया था।

क्या भारत, चीन और अन्य उभरते बाज़ार पश्चिमी देशों की कमजोरी का फायदा उठाएंगे?

- सवाल यह है कि क्या भारत, चीन और अन्य उभरते बाज़ार पश्चिमी देशों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिये अब एक मज़बूत रणनीति तैयार कर सकते हैं?
- इसके लिये दो महत्त्वपूर्ण स्थितियों की आवश्यकता होगी। पहली, चीन और अन्य उभरते बाज़ारों के बीच बेहतर संबंध। दूसरी, आर्थिक दगिगजों के

साथ प्रतस्पर्द्धा करने के लिये अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना ।

- भारत को आंतरिक सुधारों की ज़रूरत है, जबकि चीन पहले से ही ऐसा करता आ रहा है । जनसंख्या का आकार पर्याप्त नहीं है ।
- उदाहरण के लिये, भारत और चीन को अपनी न्यायिक और शैक्षणिक प्रणाली में सुधार करना है । आंतरिक शासन क्षमताओं के लिये गहरे संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता होती है ।

G-20 व G-7 वभिजन की राह पर

- बहुपक्षीय स्तर पर जी-20 समूह, जी-7 से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होगा ।
- कोई भी समूह जो अर्थव्यवस्था या सुरक्षा पर वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है तो वह सफल नहीं होगा जब तक कि इसमें ब्रिक्स देशों को शामिल न किया जाए।
- जी-7 की तरह जी-20 भी गतिशीलता बनाए रखने में सक्षम नहीं है क्योंकि पुरानी और उभरती शक्तियों के बीच एक स्पष्ट वभिजन दिखाई देता है ।
- शंघाई सहयोग संगठन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे फोरम वैश्विक नेतृत्व की नई संभावनाओं को इंगति करते हैं क्योंकि यहाँ एशियाई देश प्रभावशाली हैं ।
- पश्चिम में तकरार का माहौल दिखाई दे रहा है जसि रूस चुपचाप देख रहा है और चीन तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में एशिया के उदय के लिये केंद्रित समन्वय की ज़रूरत है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-dividers-are-divided>

